नईदुनिया

वैश्विक कमजोरी और ईरान-अमेरिका तनाव से डगमगाया शेयर बाजार मानसून की उम्मीदें और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बढ़ा मनोबल

मुंबई

भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा, जो वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत घरेलू संकेतों के बीच झूलता रहा। सप्ताह की शुरुआत शानदार तेजी से हुई, लेकिन बुधवार को एक बड़े भूचाल ने निवेशकों को हिला दिया। हालांकि, बाजार ने हार नहीं मानी और सप्ताह के अंत तक जोरदार वापसी करते हुए निवेशकों को कुछ राहत दी।

सप्ताह की शुरुआत सोमवार को जोरदार बढ़त के साथ हुई, जब मानसून की उम्मीदें और विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से निवेशकों का मनोबल बढ़ा। सेंसेक्स 521 अंक और निफ्टी 24,400 के पार बंद हुआ, हालांकि व्यापक बाजार का रुझान नकारात्मक था, जो चुनिंदा शेयरों तक ही तेजी सीमित होने का संकेत था।

मंगलवार को शुरुआती तेजी के बाद बाजार में हल्की कमजोरी दिखी और दोनों सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे चार दिनों की बढ़त का सिलसिला टूट गया। सप्ताह का सबसे बड़ा झटका बुधवार को लगा, जब वैश्विक बाजारों में कमजोरी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से भारतीय बाजार में भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स 1,677 अंक और निफ्टी 581 अंक लुढ़ककर 23,900 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे बंद हुआ।

इस ब्लैक डे पर निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए, जिससे बीएसई का कुल मार्केट कैप घटकर 472 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। हालांकि बाजार ने गुरुवार को शुरुआती रिकवरी दर्ज की, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली। सेंसेक्स 238 अंक और निफ्टी 80 अंक से अधिक बढ़कर बंद हुए। सप्ताह का अंत शुक्रवार को जोरदार तेजी के साथ हुआ, जिसने निवेशकों को गदगद कर दिया। सेंसेक्स 827 अंक और निफ्टी 244 अंक बढ़कर बंद हुए। इस तेजी के साथ सेंसेक्स 77,569.39 और निफ्टी 24,206.90 के स्तर पर पहुंच गए। कुल मिलाकर यह सप्ताह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अत्यधिक अस्थिर रहा, लेकिन घरेलू कारकों और मजबूत खरीदारी के दम पर बाजार ने बुधवार के बड़े झटके से उबरने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई।

न्यूज ब्रीफ

एप्पल ने ओपनएआई पर ठोका ट्रेड सीक्रेट चोरी का मुकदमा, पूर्व कर्मचारियों के जरिए गोपनीय डेटा चुराने में मदद का आरोप

मुंबई। दुनिया की दो दिग्गज टेक कंपनियों एप्पल और चैटजीपीटी बनाने वाली ओपनएआई के बीच गोपनीय जानकारी को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। एप्पल ने अमेरिका की एक अदालत में ओपनएआई और अपने दो पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि एप्पल की गोपनीय हार्डवेयर जानकारी और ट्रेड सीक्रेट का उपयोग कर ओपनएआई अपने एआई हार्डवेयर बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, ओपनएआई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एप्पल का दावा है कि उसके पूर्व कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ने के बाद या उससे पहले गोपनीय दस्तावेजों और तकनीकी जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बनाई, संवेदनशील फाइलें डाउनलोड या ट्रांसफर कीं। कंपनी का आरोप है कि इस जानकारी का उपयोग भविष्य के एआई-आधारित डिवाइस बनाने में किया जा सकता है। मुकदमे में, एप्पल ने एक कर्मचारी पर नौकरी छोड़ने के बाद भी नेटवर्क से गोपनीय हार्डवेयर फाइलें डाउनलोड करने और दूसरे पर इस्तीफा देने से पहले सप्लायर नेटवर्क की जानकारी निजी ईमेल पर भेजने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला सिर्फ गोपनीय जानकारी तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य के एआई हार्डवेयर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ा है। रिपोर्ट है कि ओपनएआई ऐसे एआई डिवाइस पर काम कर रहा है जो पारंपरिक स्मार्टफोन पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे आईफोन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। ओपनएआई ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका ध्यान केवल ऐसी नई तकनीक विकसित करने पर है जो दुनिया भर के लोगों को लाभ पहुंचाए।

पोस्ट आफिस आरडी योजना, छोटे निवेश से बनाएं लाखों का बड़ा फंड

नई दिल्ली। आज के समय में सुरक्षित निवेश और आकर्षक रिटर्न की तलाश हर किसी को होती है। ऐसे में भारतीय डाकघर की रिकरिंग डिपाजिट (आरडी) स्कीम आम नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय और बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। यह सरकारी छोटी बचत योजना कम जोखिम पर भविष्य के लिए एक मजबूत फंड तैयार करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। आप इस योजना में न्यूनतम 100 प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। वर्तमान में इस पर 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है, हालांकि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तिमाही आधार पर संशोधित की जाती हैं। इसकी मूल परिपक्वता अवधि 5 साल है, जिसे निवेशक अपनी सुविधा अनुसार अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि एक साल तक नियमित जमा के बाद जमा राशि के 50 फीसदी तक लोन की सुविधा भी मिलती है। जरूरत पड़ने पर तीन साल बाद समय से पहले खाता बंद करने का विकल्प भी उपलब्ध है, हालांकि ऐसे में ब्याज दर बदल जाती है। यह योजना हर वर्ग के लिए सुलभ है, जहां नाबालिगों के लिए अभिभावक द्वारा और संयुक्त खाते की सुविधा भी है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हर महीने 9500 रुपए जमा करता है, तो 5 साल में उसे लगभग 6.77 लाख रुपए (जिसमें 1.07 लाख ब्याज होगा) मिलेंगे।

भारत का लक्ष्य, 2030 तक 150 अरब डालर का इलेक्ट्रानिक्स निर्यात

नई दिल्ली। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 150 अरब डालर (लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये) के

महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रानिक्स निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने हेतु उद्योग जगत के साथ एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स उद्योग तेजी से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर निर्भर है। उन्होंने भारत की नीतिगत व्यवस्था में स्थिरता और स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि देश इन मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। अग्रवाल ने सुझाव दिया कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियां और निर्यात-आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अलग-अलग हो सकती हैं। चिंतन शिविर में वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स व्यापार में लगभग 90 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली मूल्य श्रृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।

एक्साइड इंडस्ट्रीज को बेंगलुरु प्लांट से तीसरी तिमाही में राजस्व की उम्मीद, प्रोजेक्ट पर 4,802 करोड़ खर्च कर चुकी है कंपनी

नई दिल्ली

एक्साइड इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से उसके बेंगलुरु स्थित लिथियम-आयन सेल विनिर्माण संयंत्र से राजस्व आना शुरू हो जाएगा। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। कंपनी ने इस परियोजना पर अब तक लगभग 4,802 करोड़ रुपये का निवेश किया है और चालू वित्त वर्ष में 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना है, जिससे कुल निवेश 6,202 करोड़ रुपये हो जाएगा।

राय ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि लिथियम-आयन व्यवसाय को चालू करना और उसका विस्तार करना कंपनी की पहली प्राथमिकता है, जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बढ़ती मांग से बल मिल रहा है। कंपनी 6 गीगावाट प्रति घंटे की क्षमता के साथ आगे बढ़ रही है और इसे 12 जीडब्ल्यूएच तक बढ़ाने की योजना , ताकि भारत के ऊर्जा बदलाव का 2030 तक लाभ उठाया जा सके। मोबिलिटी और स्टेशनरी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए चुनिंदा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) और अन्य ग्राहकों के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। कंपनी के प्रांतिज (गुजरात) संयंत्र के जरिये इसके माड्यूल और पैक का कारोबार भी परिचालनगत मौजूदगी दर्ज कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी अपने प्रमुख लेड-एसिड बैटरी कारोबार को भी संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने इस बाजार को 45,000 करोड़ रुपये का बताते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में इसके 55,000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे इसमें भी वृद्धि की राह बनी रहेगी।

ज्यादातर लोग नहीं जानते कंपनियों के नामों के पीछे का इतिहास

नई दिल्ली। भारतीय और वैश्विक बाजार में राज करने वाली तीन बड़ी कंपनियां बीएमडब्ल्यू, टीवीएस और एमजी के छोटे-छोटे नामों के पीछे का इतिहास ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आटोमोबाइल कंपनियां अक्सर अपने छोटे नामों से पहचानी जाती हैं, जो ग्राहकों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हम रोजाना इनकी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ते देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन छोटे नामों के पीछे एक लंबा और बेहद दिलचस्प इतिहास छिपा है। जर्मनी की लक्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम बेयरिस्चे मोटोरेन वेर्के है, जिसे अंग्रेजी में बावेरियन मोटर वर्क्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत साल 1916 में हुई थी और यह मूल रूप से विमानों के इंजन बनाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल और फिर कारों का निर्माण शुरू किया। बावेरियन शब्द जर्मनी के बावरिया राज्य से लिया गया है, जहाँ इसका मुख्यालय (म्यूनिख में) है। आज बीएमडब्ल्यू अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं, भारत की दिग्गज टू-व्हीलर कंपनी टीवीएस का पूरा नाम इसके संस्थापक के नाम पर आधारित है, जो टीवी सुंदरम आयंगर एंड संस) है। थिरुकुरंगुडी वेंगराम सुंदरम आयंगर ने साल 1911 में मदुरै में मद्रास की पहली बस सेवा के साथ इस व्यवसाय की नींव रखी थी। शुरुआत में यह कंपनी परिवहन और आटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी, लेकिन बाद में इसने खुद वाहन बनाना शुरू किया। आज टीवीएस मोटर कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी है, जो मोपेड से लेकर स्पोर्ट्स बाइक्स और माडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तक बनाती है। ब्रिटिश मूल की और अब वैश्विक पहचान बना चुकी एमजी का पूरा नाम मारिस गैरेजेस है। इस ब्रांड की शुरुआत साल 1924 में सेसिल किम्बर द्वारा आक्सफोर्ड में की गई थी। यह नाम इसके मालिक विलियम मारिस के मारिस गैरेजेस नाम के सेल्स और सर्विस सेंटर से प्रेरित था, जहाँ उन्होंने कारों को माडिफाई करना शुरू किया था।

पारदर्शिता से बढ़ेगा रियल एस्टेट निवेश : यूपी रेरा

यूपी में परियोजनाओं के बड़े आकार के कारण 40 फीसदी उपभोक्ता शिकायतें

नई दिल्ली

यूपी-रेरा के एक अधिकारी ने भारतीय रियल एस्टेट बाजार में पूर्ण पारदर्शिता की वकालत करते हुए कहा है कि इससे विकास कार्यों के लिए आवश्यक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने शुक्रवार को यह बात कही। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि रेरा का उद्देश्य नियमन है, नियंत्रण नहीं, बल्कि घर खरीदारों और परियोजना प्रवर्तकों के हितों में संतुलन साधना है।

उन्होंने देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आवासीय व वाणिज्यिक संपत्तियों की बढ़ती मांग का जिक्र करते हुए सभी हितधारकों से इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। अधिकारी ने रियल एस्टेट उद्योग संगठनों से क्षेत्र में हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8-9 प्रतिशत का योगदान देता है और 125 से अधिक सहायक उद्योगों को सहारा देता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के विकास के लिए निवेश का प्रवाह जारी रहना चाहिए, जिसमें नियामक प्राधिकरण की भूमिका भी अहम है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में 308 परियोजनाएं रेरा के तहत पंजीकृत हैं, जिनका औसत आकार 333 इकाइयों का है। परियोजनाओं के बड़े आकार के कारण, राष्ट्रीय स्तर पर कुल रेरा उपभोक्ता शिकायतों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। उन्होंने प्रवर्तकों, एजेंटों और घर खरीदारों सहित सभी संबंधित पक्षों की मदद से हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

पेट्रोल में एथनाल के मिश्रण से 1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची: सरकार

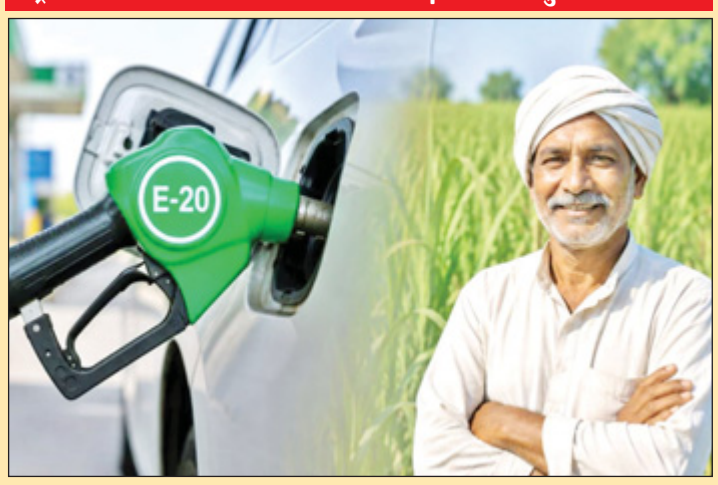

नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोल में एथनाल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि इससे चीनी उद्योग को मजबूती मिली है, किसानों की आय बढ़ी है और 2014-15 से अब तक 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने अनाज एथनाल विनिर्माता संघ (जीईएमए) के सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटी है और लगभग 930 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि एथनाल कृषि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ी, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिला और चीनी उद्योग सशक्त हुआ। उत्पादन क्षमता 21 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ लीटर हो गई है, जिसमें मक्का भी प्रमुख कच्चा माल बनकर उभरा है।

जगुआर लैंड रोवर जैसी लक्जरी गाड़ियां सस्ती होंगी

ब्रिटेन से आने वाली कारों पर सिर्फ 10 फीसदी लगेगा आयात शुल्क

नई दिल्ली

भारत सरकार ने ब्रिटेन से कार और वाहनों के आयात पर रियायती शुल्क फायदों पर एक अधिसूचना जारी की है, जो हाल ही में लागू होने वाले भारत-ब्रिटेन समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत जहां अगले 15 वर्षों में आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से कम होगा, वहीं भारतीय आटोमोबाइल उद्योग के लिए ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात के नए और बड़े अवसर खुलेंगे।

इस समझौते के तहत, भारत वाहनों पर आयात शुल्क को मौजूदा लगभग 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा। यह कटौती शुल्क दर कोटे के माध्यम से 15 साल की अवधि में चरणबद्ध ढंग से की जाएगी, जिसमें भारत के घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकीतंत्र को भी सुरक्षित रखा जाएगा। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, इस कदम से भारत के प्रीमियम वाहन बाजार में तुरंत कोई बड़ी रुकावट आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, लक्जरी खंड में धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, खासकर जैसे-जैसे शुरुआती पांच वर्षों में शुल्क घटकर 10 प्रतिशत के स्तर पर आएगा।

इससे ब्रिटेन से आयात की जाने वाली जगुआर लैंड रोवर जैसी गाड़ियां मर्सिडीज-बेंज,

बीएमडब्ल्यू और आडी के स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए माडलों के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं। आटोमोटिव इंटेलिजेंस फर्म जेएटीओ डायनामिक्स के अनुसार इस समझौते का सबसे अहम परिणाम भारत के निर्यात के लिए बना मौका है। भारत में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां (जिनकी कीमत 20,000 से 80,000 ब्रिटिश पाउंड के बीच है) ब्रिटेन के बाजार में छठे साल से बिना शुल्क के बेची जा सकेंगी। निर्यात कोटा पहले साल में 20,000 गाड़ियों से शुरू होकर 15वें साल तक 88,000 गाड़ियों तक पहुंच जाएगा। यह वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे भारतीय विनिर्माताओं के लिए दीर्घावधि में एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। समझौते के तहत शुल्क में कटौती एक बार में नहीं, बल्कि चरणों में होगी। बड़े इंजन वाली गाड़ियों के लिए ड्यूटी पहले साल में 110 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हो जाएगी और पांचवें साल तक 10 प्रतिशत पर आ जाएगी। इसी तरह मिड-रेंज गाड़ियों के लिए ड्यूटी 66 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत हो जाएगी और इसी अवधि में घटकर 10 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह समझौता व्यापार उदारीकरण और घरेलू उद्योग के बचाव के बीच संतुलन स्थापित करता है।

सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए इंट्राडे उधारी के नियम बदले, 1 सितंबर से मिलेगी अधिक सहूलियत

नई दिल्ली

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने कारोबारी सत्र के दौरान ली जाने वाली इंट्राडे उधारी के दायरे का विस्तार किया है। यह बदलाव म्यूचुअल फंड योजनाओं के संचालन में अधिक लचीलापन और दक्षता लाएगा, और नए नियम 1 सितंबर से प्रभावी होंगे। इससे पहले म्यूचुअल फंड को केवल अस्थायी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने की अनुमति थी, और वह भी कड़ी नियामकीय सीमाओं के तहत। सेबी द्वारा शुक्रवार को जारी संशोधित ढांचे के तहत, अब परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) इस उधारी का इस्तेमाल निवेश के भुगतान, रोजाना के नफा-नुकसान समायोजन, विदेशी लेनदेन निपटान और पुराने कर्ज चुकाने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए भी कर सकेंगी। नियामक का मानना है कि यह कदम विभिन्न बाजारों के अलग-अलग निपटान समय के कारण उत्पन्न होने वाले नकदी असंतुलन को

प्रभावी ढंग से दूर करेगा। सेबी ने स्पष्ट किया है कि एएमसी दिन के दौरान मिलने वाली संभावित प्राप्तियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), समाशोधन निगम और निवेशकों से प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर उधारी ले सकती हैं। हालांकि, एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सभी इंट्राडे उधार उसी दिन चुकाने होंगे। यदि कोई उधारी अगले दिन तक जारी रहती है, तो उसे ओवरनाइट उधारी माना जाएगा और उस पर अलग से नियामकीय सीमाएं लागू होंगी।

एसबीआई फंड्स आईपीओ से पहले बड़ा खुलासा, 30 साल पुराने दस्तावेज़ गायब, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में माना, 11,693 करोड़ के आईपीओ पर गहराया संदेह

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित आईपीओ इस हफ्ते बाजार में दस्तक देने वाला है। हालांकि, इश्यू से ठीक पहले कंपनी ने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसके कुछ बेहद महत्वपूर्ण और लगभग तीन दशक पुराने रिकार्ड्स और दस्तावेज गायब हो गए हैं, जिन्हें वह लाख कोशिशों के बाद भी खोज नहीं पा रही है। गायब हुए दस्तावेज करीब तीन दशक पुराने हैं, जिनमें 30 जून, 1992 के अतिरिक्त इश्यू और 7 नवंबर, 1997 के राइट्स इश्यू से जुड़े आफर और अलाटमेंट लेटर शामिल हैं। कंपनी ने इन दस्तावेजों को खोजने के लिए एक स्वतंत्र कंपनी सेक्रेटरी फर्म को भी लगाया, जिसने रजिस्ट्रार आफ कंपनीज (आरओसी), एमसीए पोर्टल्स और कंपनी के रजिस्टर्ड आफिस में गहन तलाशी ली, लेकिन रिकार्ड्स का पता नहीं चल सका। आरएचपी में कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इन गायब दस्तावेजों को लेकर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही या पेनल्टी नहीं चल रही है। हालांकि, कंपनी यह आश्वासन नहीं दे सकती कि भविष्य में गुम दस्तावेजों के संबंध में उसके विरुद्ध कोई कानूनी या नियामकीय कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।